3 साय को मिली जन-जन की शुभकामनाएं

5 रेखा गुप्ता के हाथों में दिल्ली की कमान

8 मोदी को मोहित करने में लगे मोहन यादव

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 42 प्रति सोमवार, 24 फरवरी 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

क्या सिर्फ़ कमाई के लिए खनन, वन, पर्यावरण, गृह, जनसंपर्क जैसे संसाधनों वाले विभागों पर कुंडली जमाए बैठे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव?

मुख्यमंत्री सरकार के आधे से अधिक विभागों के मंत्री बन बैठे

अनुभवी मंत्रियों के कामकाजों में अड़ंगा लगा रहे मोहन यादव

कवर स्टोरी

-विजया पाठक

एडिटर

भारत के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपनी ही कैबिनेट में आधा दर्जन से ज्यादा मन्त्रालय अपने पास रखे हैं। काम की समीक्षा करें तो इनके सारे विभागों का रिपोर्ट कार्ड नैगेटिव है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने पास आधे दर्जन से अधिक विभाग रखे हुए हैं। जिनमें सब मंत्रालय महत्वपूर्ण हैं। गृह जैसा विभाग भी मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। जिसके कारण प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अपनी व्यस्तता के कारण मोहन यादव इस महत्वपूर्ण विभाग को समय ही नहीं दे पा रहे हैं और प्रदेश में नक्सली तक अपने पैर पसारने लगे हैं। पिछले महीने ही बालाघाट जिले में नक्सली मूवमेंट को देखा गया था। जहां तक जनसंपर्क विभाग की बात की जाये तो प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब जनसंपर्क विभाग में अव्यवस्थित तरीके से कामकाज चल रहा है। जो पत्रकार सरकार में पनपे भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखते हैं या दिखाते हैं उनकी अभिमान्यता तक खत्म करने की ओछी हरकत करते हैं। 06-06 महीनों तक विज्ञापनों को पेमेंट नहीं हो रहा है। छोटे-छोटे अखबारों, पत्र-पत्रिकाओं को साल में दो बार भी विज्ञापन नहीं मिल रहा है। विभाग में बैठे अधिकारी अपनी मनमर्जी चलाकर पत्रकारों को परेशान करने पर तुले हैं। विज्ञापनों पर करोड़ों रूपये फूंकने के बाद भी सरकार की छवि धूमिल हो रही है। क्योंकि ज्यादातर पत्रकार सरकार की नीति और नियत से परेशान हैं। विभाग के मुखिया मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। या कहे तो उन्हें ध्यान देने के लिए समय ही नही है। अन्य मलाईदार विभाग, जिनके मुखिया खुद मोहन यादव हैं उनकी बात करें तो कमोबेश यही स्थिति है। मुख्यमंत्री मलाई खाने के चक्कर में राजस्व का पलीता लगा रहे हैं। खनिज जैसे महत्वत्वपूर्ण विभाग, जिससे प्रदेश को काफी राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन मुख्यमंत्री अपनी झोली भरने के चक्कर में खनिजों की लूट की खुली छूट दे रखे हैं। प्रदेश में बड़े स्तर पर अवैध उत्खनन का धंधा फल फूल रहा है।

(शेष पेज 2 पर)

पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लिया जिले का प्रभार

छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को मिली जीत, जनता ने सरकार की नीतियों पर लगाई मुहर

राज्य में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण हुआ संपन्न, 77.06 प्रतिशत हुआ

-विजया पाठक

राजनैतिक दलों में इस बात को लेकर खासी चर्चा है कि जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को पटकनी दी है, उसी तरह एक बार फिर पंचायत चुनावों में कांग्रेस को हार का मुंह दिखाने के लिये उत्सुक है। राज्य के मुखिया विष्णुदेव साय ने भाजपा को मिली बड़ी बढ़त के बाद प्रदेश की जनता का आभार जताया। सीएम ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लोगों के विश्वास का नतीजा बताया. उनके मुताबिक जनता ने सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई है।

वादा पूरा करने के लिए आए

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जनता ने देश के पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। इस जीत के लिए मैं छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। सबने अटल विश्वास पत्र पर भरोसा जताया। मुख्यमंत्री होने के नाते वादा करता हूं कि जो भी वादा अटल विश्वास पत्र में किया है, वह पूरा होगा। हम लोगों को ठगने के लिए नहीं बल्कि वादा पूरा करने के लिए आए हैं। सीएम साय ने पिछले चुनाव के नतीजों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तब कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी। महापौर और अध्यक्ष चुनाव को प्रत्यक्ष नहीं कराया था, लेकिन इस बार हमने जनता को उनका हक दिया और लोकतंत्र की जीत हुई।

पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत पाई कांग्रेस

मुख्यमंत्री ने कहा कि रायपुर में पिछले बार के कांग्रेस से जीते महापौर इस बार पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत पाए। आगे कहा, 10 नगर निगम के चुनाव हुए, जिसमें हमें जीत मिली। सभी ने अच्छे अंतर से जीत दर्ज की है। 49 नगर पालिका में से 33 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, वहीं 114 नगर पंचायत में 84 में हम जीत चुके हैं और परिणाम डिक्लेयर होते-होते तस्वीर और खूबसूरत होगी।

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव परिणाम आने के बाद अब पंचायतों में चुनावी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। राज्य के पंचायतों में दूसरे चरण का मतदान पूरा हो गया है जिसमें 77.06 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

(शेष पेज 2 पर)

बच्चे भारत का भविष्यः आजीवन स्वस्थ्य उत्पादकता और कल्याण की नींव बचपन में ही रखी जा सकती है

किशन भावनानी
एडवोकेट

वैश्विक स्तर पर हम मनीषी जीव के अनेक रूप देखते हैं, कोई सड़क पर भीख मांग रहा है तो कोई विश्व का सबसे अमीर है। कोई स्वास्थ्यता से डैमेज होकर दिव्यांग है तो कोई विश्व का सबसे स्वस्थ व्यक्ति! कोई बच्चा फुटपाथ पर जीवन जी रहा है तो कोई महलों में है। हालांकि इस स्थिति को किस्मत का खेल भी हम मानते हैं परंतु इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि अगर एक माली या किसान जमीन में कोई बीज बोकर उसका सतर्कता से ध्यान रखना है, अंकुरित होकर पौधा होने तक उसका पूरा ध्यान रखना है तो अधिकतम संभावना उसके फलदार वृक्ष बनकर आजीवन स्वस्थ उत्पादकता बनी रहती है, जिसकी नींव उसे अंकुरित बीज की देखभाल करने से पड़ी। ठीक उसी तरह अगर हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य, जीवन शैली, स्वस्थ्य विकास, गुणवत्ता सुधार पर उनके बचपन से ही गंभीरता व सतर्कता से ध्यान देंगे तो उनमें गुण ही अंकुरित होते जाएंगे उनके स्वास्थ्य व स्वस्थ्य विकास के फल उनके जीवन पर्यंत मिलेंगे, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, आओ बच्चों में स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता सुधार स्वास्थ्य विकास रूपी बीज बोकर उन्हें जीवन पर्यंत स्वस्थ व फलदार वृक्ष रूपी गुणवान बनाएं।

बात अगर हमः हम बच्चों के स्वास्थ्य की करें तो परिवार और उनकी मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करने वालों के प्रति अपना समर्थन दिखाते हैं परिवार की आय बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख कारक है। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक

बच्चों के उपचार के लिए कोई समर्पित सुविधा नहीं थी। उनका इलाज घर पर ही किया जाता था और अगर परिवारों के लिए यह विकल्प नही होता था, उस समय बच्चों के स्वास्थ्य की समझ को परिभाषित नहीं किया गया था और अक्सर परित्यक्त और अनाथ बच्चों को शिशु आश्रय गृहों में छोड़ दिया जाता था। अब समय के विकास के साथ बच्चों के स्वास्थ्य और गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बात अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक बाल स्वास्थ्य एजेंडे की करें तो, पिछले दशकों में 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जीवित रहना वैश्विक बाल स्वास्थ्य एजेंडे का मुख्य केंद्र रहा है। परिणामस्वरूप, 1990 और 2019 के बीच वैश्विक बाल मृत्यु दर में 60 प्रतिशत की कमी आई। 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होने वाली 5.2 मिलियन मौतों में से कई मौतें कमजोर आबादी में केंद्रित थीं, विशेष रूप से उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में !इस बात के प्रमाण के आधार पर कि आजीवन स्वास्थ्य, उत्पादकता और कल्याण की नींव बचपन में ही रखी जाती है, स्वास्थ्य क्षेत्र की यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है कि बच्चे न केवल जीवित रहें,बल्कि फलते- फूलते रहें। सतत विकास लक्ष्यों में छोटे बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट लक्ष्य शामिल हैं, जो मानव पूंजी उत्पन्न करता है जो हर बच्चे का अधिकार है, और न्यायसंगत और सतत प्रगति के लिए आवश्यक है। एक सुरक्षित, स्वस्थ और सुरक्षात्मक वातावरण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी बच्चे अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ सकें और विकसित हो सकें। बता दें 12-14 नवंबर 2024 को मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य और पोषण के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के विशेषज्ञों की 10 वीं बैठक का एजेंडा विश्व बैंक द्वारा तैयार कर लिया गया है। बचपन की बीमारियों का प्रबंधन गुणवत्तापूर्ण, बाल-केंद्रित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के कार्यान्वयन का समर्थन करके,डब्लू एचओ देशों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में काम करने में मदद करता है। उसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे अपना 10 वां जन्मदिन अच्छे स्वास्थ्य में मना सकें।स्वास्थ्य सुविधाओं में लाए गए बच्चे अक्सर एक समय में एक से अधिक स्थितियों से पीड़ित होते हैं और पर्याप्त देखभाल प्रदान करना एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। कम संसाधन वाले देशों में प्रथम स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं में रेडियोलॉजी और प्रयोगशाला सेवाओं जैसे नैदानिक समर्थन न्यूनतम या न के बराबर होते हैं और दवाएँ और उपकरण अक्सर दुर्लभ होते हैं। इन सीमाओं के बावजूद उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल सुनिश्चित करने के लिए, डब्ल्यूएचओ बचपन की बीमारी के एकीकृत प्रबंधन के निरंतर कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। निमोनिया, दस्त, मलेरिया खसरा और कुपोषण। इसके तीन घटक हैं: स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के केस प्रबंधन कौशल में सुधार, समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार, और परिवार और सामुदायिक प्रथाओं में सुधार।प्रसार वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। इसे 10 वर्ष तक के बच्चों तक विस्तारित करने के लिए चर्चा चल रही है

छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को मिली जीत, जनता ने सरकार की नीतियों पर लगाई मुहर

(पेज 1 से जारी)

राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार राज्य के 43 विकासखंडों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रही। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दूसरे चरण में 77.06 प्रतिशत मतदान हुआ। कई मतदान केंद्रों से अंतिम मतदान के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सकती है। मतदान मतपत्रों के माध्यम से हुआ।

तीन स्तरों पर होते हैं चुनाव

राज्य में पंचायत के चुनाव तीन स्तरों पर होते हैं- ग्राम पंचायत (गांव), जनपद पंचायत (ब्लॉक) और जिला पंचायत (जिला)। पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते। दूसरे चरण के लिए 43 विकासखंडों में 9,738 मतदान केंद्र बनाए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि दूसरे चरण में वार्ड पंच के लिए 65,716, सरपंच के लिए 15,217, जनपद पंचायत सदस्यों के लिए 3,885 और जिला पंचायत सदस्यों के लिए 699 उम्मीदवार मैदान में थे। उन्होंने बताया कि 17 फरवरी को पंचायत चुनाव के पहले चरण में 27,210 वार्ड पंच, 3,605 सरपंच, 911 जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के 149 पदों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें 81.38 प्रतिशत मतदान हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक चरण में वोट डाले जाने के तुरंत बाद संबंधित मतदान केंद्रों पर मतगणना की जा रही है।

एक लाख वोटों से जीतीं मीनल चौबे

उल्लेखनीय है कि रायपुर से महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे 1 लाख से भी ज्यादा मतों से जीत गई हैं। वो अब तक नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थीं। तीन बार की पार्षद रहीं हैं। वहीं, कोरबा नगर निगम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी की महापौर प्रत्याशी संजू देवी राजपूत की जीत पक्की मानी जा रही है। वहीं, पार्षद पद पर भी बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है, जहां पार्टी के 52 पार्षदों ने जीत दर्ज की है।

क्या सिर्फ़ कमाई के लिए खनन, वन, पर्यावरण, गृह, जनसंपर्क जैसे संसाधनों वाले विभागों पर कुंडली जमाए बैठे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव?

(पेज 1 से जारी)

वैसे भी मोहन यादव पर बदनुमा दाग लगा है कि वह भोपाल से ज्यादा समय उज्जैन में बिताते हैं। आधे से ज्यादा समय उड़नखटोले में बिताते हैं। इसके उपर यह और है कि मोहन यादव महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया बने बैठे हैं। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि समय न होने के कारण मुख्यमंत्री अपने विभागों की समीक्षा महीनों तक नहीं करते हैं। जिसके कारण फाइलें मूव ही नही होती हैं। फाइलें मूव नही होती तो कामकाज बाधित होता है। यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि कोई मुख्यमंत्री अपने पास इतने सारे और महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हुए हैं। मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अपने पास नीतिगत मामलों के विभाग, सामान्य प्रशासन और नर्मदा विकास प्राधिकरण जैसे विभाग ही रखते थे। लेकिन मोहन यादव एक ऐसे राज्य के प्रमुख हैं जो अपने पास गृह एवं खनिज, जेल, वन एवं पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हुए हैं। मोहन यादव की नई परंपरा के कारण न तो सरकार का संचालन ठीक से हो रहा है और न ही मंत्रीमंडल के अपने साथियों के साथ बेहतर तालमेल हो पा रहा है। आज प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रशासन स्तर पर तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। इसके अलावा मंत्रीमंडल के साथियों के साथ भी मोहन यादव बेहतर तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। और उनके मंत्रालय के अधिकारों में भी अड़ंगा लगाकर माहौल को खराब करते हैं। कई अनुभवी मंत्री मुख्यमंत्री के बर्ताव से नाराज दिखाई देते हैं। विभाग के प्रमुखों के साथ भी मोहन यादव अभद्र व्यवहार करते हैं। अन्य बीजेपी राज्यों की बात की जाये तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने भी अपने पास महत्वपूर्ण विभाग नही रखे हैं।

प्रदेश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने लिया जिले का प्रभार

राजनैतिक विश्लेषकों की मानें तो मध्यप्रदेश की स्थापना के बाद से लेकर अभी तक का इतिहास अगर देखा जाये तो यह पहला अवसर है जब मध्यप्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने जिले का प्रभार अपने पास रखा है। यही नहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह निर्णय किस उद्देश्य के साथ लिया गया है यह भी जगजाहिर हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मुखिया होता है। ऐसे में किसी जिले का प्रभार लेना न तो नियमानुसार ठीक है और न ही संवैधानिक रूप से उचित है क्योंकि मुख्यमंत्री को पूरे समय प्रदेश के विकास और जनकल्याण की दिशा में कार्य करना होता है। ऐसे में जिले का प्रभार लेकर वे कैसे अन्य जिलों के साथ न्याय कर सकते हैं।

हवाई खर्चों और प्लेन खरीदने में किया जा रहा है पैसा बर्बाद

मध्यप्रदेश की वित्तीय स्थिति काफी दयनीय है, किन्तु वित्तीय व्यय को सीमित करने की जगह मुख्यमंत्री अपनी विलासिता के लिए खर्च कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विमानन विभाग के मंत्री भी हैं। बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश की इतनी बुरी माली हालत के बाद मुख्यमंत्री ने पिछले एक साल में फिजूलखर्ची कर जनता के पैसों में आग क्यों लगा रहे है। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और एक दो शहरों को छोड़कर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा खरीदे गए 233 करोड़ के चैलेंजर-3500 बॉम्बार्डियर प्लेन, प्रदेश के ज्यादातर हवाई पट्टियों पर उतर ही नहीं पाएगा। टेक्निकली इन हवाई पट्टियों का आकार बॉम्बार्डियर प्लेन को लैंड कराने लायक ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने एक साल में 486 से अधिक यात्राएं कर डाली हैं, इनमें से केवल उज्जैन-इंदौर के लिए 150 से अधिक बार हवाई यात्राएं की। इसका मतलब मुख्यमंत्री उज्जैन से भोपाल अप-डाउन करते थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मिली जन-जन की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री ने जनता का आभार जताया, प्रदेश के विकास में निरंतर समर्पण का संकल्प

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के जन्मदिन पर राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास देर रात तक उल्लास और स्नेह के वातावरण से भरा रहा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, उद्योगपतियों, समाजसेवियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएँ दीं। मुख्यमंत्री साय ने सभी आगंतुकों से आत्मीयता से मुलाकात की और स्नेह, सम्मान और शुभकामनाओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आप सभी के प्रेम और सहयोग से मैं अभिभूत हूँ। छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना है। आपका निरंतर समर्थन और आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, यही मेरी कामना है। मुख्यमंत्री निवास में मंत्रीगण, विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री साय को बधाई दी। इस अवसर पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दीं। इसके साथ ही विधायकगण धरमलाल कौशिक, राजेश मूणत, सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, गजेन्द्र यादव, मोतीलाल साहू, गुरु खुशवंत साहेब, दीपेश साहू और ललित चन्द्राकर ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री साय को प्रदेश के उद्योगपतियों, व्यापारी संगठनों, खेल जगत के प्रतिनिधियों, समाजसेवियों, शिक्षाविदों और मीडिया जगत के वरिष्ठ जनों ने भी शुभकामनाएँ दीं। सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री को शुभकामनाओं का तांता लगा रहा, जहां हजारों लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके नेतृत्व में प्रदेश के विकास की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर सभी का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास और समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और विकसित प्रदेश बनाने के लिए सरकार प्रत्येक वर्ग के हित में कार्य कर रही है और यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

राजिम कुंभ मेला में कोसा की प्रदर्शनी आकर्षण का केन्द्र

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। राजिम कुंभ कल्प मेला में गरियाबंद जिले के विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में ग्रामोद्योग विभाग के रेशम प्रभाग का स्टाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्टाल में किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों को कोसा उत्पादन की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। अब तक हजारों लोग इस स्टाल पर पहुंचकर कोसा उत्पादन की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। कोसा उत्पादन किसानों के लिए न केवल आय का एक अतिरिक्त जरिया बन सकता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाने में मददगार होगा। स्टाल प्रभारी राम गोपाल चौहान ने बताया कि कोसा उत्पादन वन एवं कृषि आधारित रोजगार का एक बेहतरीन जरिया है, जिससे गांवों में ही आजीविका प्राप्त की जा सकती है। छत्तीसगढ़, जो हरितिमा से आच्छादित राज्य है, में खेतों के किनारे अर्जुन के पेड़ लगाकर कोसा उत्पादन किया जा सकता है। अर्जुन पेड़ों की पत्तियों पर कोसा कीड़े तीस दिन में कोसा फल तैयार कर देते हैं, जिसे किसान आसानी से बाजार में बेच सकते हैं। कोसा उत्पादन कृषि के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इसका पालन खेतों में बायो-फर्टिलाइजर के रूप में भी उपयोगी होता है। प्रति अर्जुन वृक्ष 50 से 60 कोसा फल उत्पन्न होते हैं, जो बाजार में एक से दो रुपये प्रति फल की दर से बिकते हैं। इस प्रक्रिया में 70 प्रतिशत कोसा फल तोड़कर बेचा जाता है, जबकि 30 प्रतिशत को प्राकृतिक वंश वृद्धि के लिए पेड़ों पर ही छोड़ना आवश्यक होता है, जिससे आगे कोसा तितलियां विकसित होकर उत्पादन की श्रृंखला को बनाए रखें।

एम्स भोपाल में 'ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन टेस्टिंग: बेसिक टू एडवांस' पर वर्कशॉप

-समता पाठक

जगत प्रवाह. भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड बैंक विभाग ने 21 फरवरी 2025 को "ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इंफेक्शन टेस्टिंग: बेसिक टू एडवांस" पर एक सतत चिकित्सा शिक्षा (CME) कम कार्यशाला का सफल आयोजन किया। इस सीएमई को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें विभिन्न संस्थानों के 150 से अधिक चिकित्सा पेशेवरों ने भाग लिया। इस वर्कशॉप का उद्देश्य ट्रांसफ्यूजन-ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन (TTI) टेस्टिंग की मौलिक अवधारणाओं और उन्नत डायग्नोस्टिक तकनीकों को गहराई से समझाना था। इस वर्कशॉप के महत्व को रेखांकित करते हुए, प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा "रक्त आधान (ब्लड ट्रांसफ्यूजन) की सुरक्षा सुनिश्चित करना स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण पहलू है और ट्रांसफ्यूजन-ट्रांसमिटेड संक्रमणों की सटीक जांच जटिलताओं को रोकने के लिए आवश्यक है। यह सीएमई-कम-वर्कशॉप एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा पेशेवरों को नवीनतम ज्ञान और व्यावहारिक कौशल से सुसज्जित करना है ताकि रक्त संक्रमण सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ाया जा सके।" इस वर्कशॉप में एमजीएम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, एम्स नागपुर और एम्स भोपाल जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रख्यात अतिथि वक्ता ने अपने अनुभव और ज्ञान साझा किए। वैज्ञानिक सत्रों में टीटीआई टेस्टिंग में नवीनतम प्रगति पर चर्चा की गई, जबकि शाम के सत्र में ईएलआईएसए तकनीक और गुणवत्ता नियंत्रण उपायों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण प्रयोगशाला प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ। इस सीएमई-कम-वर्कशॉप ने ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, प्रयोगशाला डायग्नोस्टिक्स और संक्रमण नियंत्रण से जुड़े स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण और प्रशिक्षण अवसर प्रदान किया, जिससे रोगी देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार हुआ।

राधास्वामी की जमीन की लीज समाप्त करने खेल प्रेमी कोर्ट में बनेंगे तीसरी पार्टी

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। राधास्वामी संस्था के विरोध में शीघ्र ही नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी पार्षद, पूर्व जनप्रतिनिधि, पूर्व खिलाड़ी व खेल संगठन के सदस्य जबलपुर हाईकोर्ट में इंटरवेंशनल याचिका लगाएंगे। नगर में खेल मैदान की मांग के मामले में कोर्ट में चल रहे प्रकरण में यह तीसरा पक्ष रहेगा। शासन द्वारा राधास्वामी संस्था के पास मौजूद 3/47 एकड़ भूमि की लीज नवीनीकरण के मामले में अब तीसरे पक्ष की ओर से अपनी बात कोर्ट में रखी जाएगी। इसके लिए नगर के वरिष्ठजनों ने जबलपुर पहुंचकर वकील से सम्पर्क किया इस कार्य में सभी नगरवासी एकजुट नजर आ रहे हैं।

तीसरी पार्टी बन जानेंगे प्रकरण में क्या चल रहा है

पूर्व क्रिकेटर दीपक पटवारे और कबड्डी कोच अंकित जोशी ने बताया कि लंबे समय से कोर्ट में यह प्रकरण चल रहा है। हम तीसरी पार्टी बनकर यह जान सकेंगे आखिर प्रकरण में क्या चल रहा है। कब क्या हो रहा है इसके लिए नगर के लोगों से खूब सहयोग मिल रहा है। प्रकरण में खर्च के लिए अब तक करीब 40 हजार रूपए एकत्रित कर लिए हैं।

यह लोग रखेंगे अपना पक्ष

राधास्वामी सत्संग हाईस्कूल के आधिपत्य की शासकीय भूमि की लीज के नवीनीकरण की कार्यवाही हरदा में चल रही है। जिस पर रोक लगाने एवं शासन की भूमि को नगरपरिषद को सौंपकर खेल मैदान बनाने के लिए टिमरनी के समाजसेवी पार्षद खेल प्रशिक्षक एवं समस्त नगरवासियों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है। इस कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने के उद्देश्य से राधास्वामी संस्था द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश अपने पक्ष में ले लिया है। उसे समाप्त करने के लिए एवं उच्च न्यायालय में चल रहे प्रकरण में पार्टी बनने के लिए नगर के वरिष्ठजनों ने जबलपुर जाकर अधिवक्ता से संपर्क किया एवं शीघ्र ही उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही में भी नगर एवं खेल प्रेमियों की ओर से अधिवक्ता नियुक्त होकर पैरवी भी करेंगे।

सम्पादकीय

दिल्ली के सिंहासन का ताज: रजिया सुल्तान से लेकर रेखा गुप्ता तक

रेखा गुप्ता ने राजधानी के रामलीला मैदान पर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब वहां से कुछ दूरी पर दिल्ली 6 की एक गली में सन्नाटा था। इसका नाम है बुलबुलीखाना। यहां चारों तरफ से घिरे हुए परिसर में चिर निद्रा में हैं रजिया सुल्तान। यहां की हालत को देखकर समझ आता है कि इधर अब शायद ही कोई उस रजिया सुल्तान की कब्र पर फूल चढ़ाने आता हो जिसने 1236-1240 के बीच दिल्ली पर राज किया था। इधर लगे एक शिलापट्ट पर बताया गया है कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के प्रमुख शासक इल्तुतमिश की बेटी थीं। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनाया दिया था। उसे अपने किसी भी पुत्र में दिल्ली पर राज करने की कुव्वत नजर नहीं आती थी।

बहरहाल रजिया सुल्तान के राज के सात सौ साल से भी अधिक समय के बाद शीला दीक्षित 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनीं। उन्होंने लगातार 15 सालों तक दिल्ली पर राज किया। इतने लंबे समय तक दिल्ली पर शायद ही किसी शासक ने लगातार राज किया हो। अगर मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित का कार्यकाल सबसे लंबा रहा तो सुषमा स्वराज का कार्यकाल दो महीने भी नहीं रहा। वो 12 अक्तूबर 1998 से लेकर 3 दिसंबर 1998 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। जाहिर है कि इतने छोटे से कार्यकाल में वो कोई अहम कदम जनता के हित में नहीं ले सकी थीं।

भाजपा आलाकमान ने साहिब सिंह वर्मा के स्थान पर सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था। अब साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश साहिब सिंह वर्मा दिल्ली की कैबिनेट में आ गए हैं। अगर आप दिल्ली की सियासत के गुजरे दौर के पन्ने खंगाले तो पता चलेगा कि डॉ. सुशीला नैयर को अज्ञात कारणों के चलते यहां के पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखा गया था। देश के पहले लोकसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव 1952 में हुआ था। उसमें कांग्रेस को अभूतपूर्व विजय मिली।

सियासत और सार्वजनिक जीवन में कामकाज के लिहाज से डॉ. सुशीला नैयर के मुख्यमंत्री बनने की पूरी उम्मीद थी। पर दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए नंगलोई के विधायक चौधरी ब्रह्म प्रकाश। उन्होंने डॉ. सुशीला नैयर को अपना स्वास्थ्य मंत्री बनाया। तब बहुत लोगों को हैरानी हुई थी कि डॉ. सुशीला नैयर को क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वो देवनगर से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई थीं। डॉ. सुशीला नैयर गांधी की शिष्य होने के साथ-साथ उनकी निजी चिकित्सक भी थीं। वो गांधी के निजी सचिव प्यारे नैयर की छोटी बहन थीं। जब गांधी जी ने 12 से 18 जनवरी, 1948 को उपवास रखा तब डॉ. सुशीला नैयर उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रही थीं। उन्होंने ही फरीदाबाद में ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम की स्थापना करवाई। उन्होंने देशभर में डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्र में जाने को प्रेरित किया। उनकी शख्सियत बहुत शानदार थी। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया।

खैर, अरविंद केजरीवाल के अचानक से इस्तीफा देने के बाद आतिशी पिछले साल 17 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनीं। अब रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री बनी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज की स्टूडेंट रही रेखा गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष भी रही हैं। उन्हें अब दिल्ली के मसलों को हल करना होगा। रेखा गुप्ता की पहली प्राथमिकता उस यमुना को स्वच्छ करना होना चाहिए जिसे दिल्ली सदियों से जमुना जी कहती है। उसके लिए यह पूजनीय है। पुरानी दिल्ली वाले इसे प्यार से और सम्मानपूर्वक अब "जमुना जी" ही कहते हैं। दिल्ली के लिए, यमुना सिर्फ एक नदी ही नहीं है। इसके पानी में स्नान करना एक आशीर्वाद माना जाता है, मोक्ष की ओर एक कदम। जब दिल्ली अपनी चारदीवारी वाले शहर तक ही सीमित थी, तो जमुना जी जीवन रेखा थीं। इसने पीने का पानी उपलब्ध कराया, अपने किनारों पर उगाई जाने वाली सब्जियों को पोषण दिया, पशुधन को पानी पिलाया, जीवंत तैराकी मेलों की मेजबानी की। दिल्ली की बुजुर्ग महिलाएं नियमित रूप से सुबह जल्दी जमुना जी जाती थीं, स्नान और ध्यान के लिए। दिल्ली में एक लंबे अंतराल के बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी के साथ, उसे यमुना को बचाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।स्थिति गंभीर है। दिल्ली में वजीराबाद से ओखला बैराज तक यमुना नदी के प्रदूषण के कई कारण हैं, जो इसे मैली बनाते हैं। रेखा गुप्ता के सामने चुनौती बड़ी है। उन्हें अपने को साबित करना होगा।

सियासी गहमागहमी

काश साल में एक बार प्रधानमंत्री हर शहर में पहुंचे

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल इन दिनों किसी दुल्हन सी सजी प्रतीत हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रदेश की राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन को लेकर जिस तरह से ताना बाना बुना गया है उसने प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। चर्चा इस बात को लेकर है कि काश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर वर्ष एक-एक शहर में जरूर जायें ताकि उस शहर का कायाकल्प हो सके। जाहिर है कि लंबे समय से प्रदेश की राजधानी को साफ-सफाई और मरम्मत की आवश्यकता थी। लेकिन मोदी के आने से यह इंतजार अब खत्म हो चला है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक दिन रात में भोपाल रूकेंगे, इसको देखते हुए हर उस स्थल पर जहां उद्योगपतियों, प्रधानमंत्री का आवागमन होना है उन्हें सजाया संवारा जा रहा है।

कांग्रेस ने खोल दी मोहन यादव की पोल

मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन को लेकर प्रदेश की मोहन सरकार को घेरा है। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से विकास और जनहित की योजनाओं का समर्थन करती रही है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि सिर्फ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने से विकास नहीं होगा, जब तक कि उन पर धरातल पर प्रभावी अमल नहीं किया जाता। पिछले इंवेस्टर समिट में जो वादे किए गए थे, वे आज तक अधूरे हैं। कई उद्योगों की घोषणाएं की गईं, लेकिन ज्यादातर या तो शुरू ही नहीं हो पाईं या फिर अधर में लटकी रहीं। सरकार को चाहिए कि वह पिछली विफलताओं की समीक्षा करे और सुनिश्चित करे कि इस बार निवेश के नाम पर किए गए समझौते वास्तव में जमीन पर उतरें। पटवारी के इस बयान के बाद भाजपा और उसके नेता बगले झांकते नजर आ रहे हैं।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
अपने साहस और शौर्य से उन्होंने हमें निडरता और पूरे समर्पण के साथ आवाज उठाने की प्रेरणा दी।

उनका जीवन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा।
-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

प्रदेश में गेहूं की फसल तैयार होने वाली है और आने वाले कुछ सप्ताह में गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

मैं भाजपा सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने किसानों को गेहूं का 2700 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का चुनावी वादा किया था।
-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

ढाई दशक बाद सत्ता में वापस आई भाजपा ने सौंपी कर्मठ महिला नेत्री रेखा गुप्ता के हाथों में दिल्ली की कमान

समता पाठक/जगत प्रवाह

27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर रही भाजपा फिर से एक महिला को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी है। दिल्ली में आखिरी बार भाजपा सरकार की मुखिया सुषमा स्वराज थीं। अब 27 साल बाद जब दिल्ली में भाजपा की नई सरकार का गठन होने जा रहा है तो फिर से दिल्ली की कमान एक महिला के हाथों में सौंपी गई है। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 50 साल की रेखा गुप्ता दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। बात रेखा गुप्ता की पढ़ाई की करें तो उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की है। रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में जींद जिले के नंदगढ़ गांव में हुआ। जब वे दो साल की थीं, उनके पिता भारतीय स्टेट बैंक में मैनेजर के पद पर नियुक्त हुए और परिवार दिल्ली चला गया। 1976 में पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया, जहां रेखा ने अपनी पढ़ाई पूरी की। रेखा गुप्ता ने अपनी शिक्षा दिल्ली में पूरी की और इसी दौरान वे एबीवीपी से जुड़ीं। उन्होंने एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। उनके परिवार के सदस्य जुलाना की अनाज मंडी में आढ़त का काम करते हैं। जब पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हुआ, तो उन्होंने अपने पुस्तैनी घर को गांव के लोगों को बेच दिया।

रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव और प्रधान भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी हैं। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को हराकर चुनाव जीता है। रेखा गुप्ता को कुल 68200 वोट मिले थे। जबकि आप की वंदना कुमारी 38605 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। यहां से कांग्रेस के प्रवीण कुमार जैन 4892 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थे।

सांसद राहुल सिंह की छबि खराब करने का आरोप, लोधी समाज और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरी। सागर जिले के देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम में सेमराखेड़ी में ढाबा संचालकों के बीच हुए विवाद मामले में दमोह सांसद राहुल सिंह की छवि खराब करने का आरोप लगा है। जिसके बाद राजनीति गरमा गई है। लोधी समाज और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। जहां पर उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से तहसीलदार संगम पटले को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा विगत 12 फरवरी को गांव के पप्पू उर्फ वृंदावन लोधी सेमराखेड़ी का गुटी खान

भाई फिरोज खान का सट्टा कारोबार को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें फिरोज खान और साथियों ने वृंदावन के साथ जमकर मारपीट कर दी थी। जिसकी देवरी थाने में रिपोर्ट दर्ज है रिपोर्ट में देवरी पुलिस ने विवाद का कारण छुपाया साथ ही मामला एक पक्षीय होने के बावजूद काउंटर मामला दर्ज किया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद गुटी, फिरोज ने अपने साथियों के साथ सागर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। जिस में दमोह सांसद राहुल सिंह, भाजपा एवं जनपद सदस्य वीरेंद्र लोधी का नाम बदनाम करने के उद्देश्य से उछाला। जो निंदनीय है। इस संबंध में प्रभारी मंत्री, देवरी विधायक सहित, भाजपा पार्टी के पदाधिकारी को भी अवगत कराया है। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के साथ सांसद की छवि खराब करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है।

बक्सर जिले को 476 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात, मुख्यमंत्री ने किया 73 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास

-अमित राय

जगत प्रवाह. पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के क्रम में बक्सर जिले को 476.02 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात दी। 73 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसके तहत 350.13 करोड़ रूपये की 41 योजनाओं का उद्घाटन तथा 125.89 करोड़ रूपये की 32 योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने बक्सर जिला अंतर्गत सिमरी बहुग्रामी जलापूर्ति योजना, केशवपुर का शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन किया। इसकी लागत 202.70 करोड़ रूपये है। उद्घाटन के पश्चात् मुख्यमंत्री ने इस बहुग्रामी जलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस बहुग्रामी पेयजल आपूर्ति प्लांट के शुरू हो जाने से सिमरी प्रखंड के 214 वार्डों में स्थित 36760 घरों में आर्सेनिक मुक्त शुद्ध गंगा जल की आपूर्ति पेयजल के रूप में होगी। बक्सर जिलांतर्गत विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। विभिन्न विभागों एवं जीविका दीदियों द्वारा लगाये गये स्टॉल का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। अवलोकन के क्रम में मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एक लाख रुपये का सांकेतिक चेक, सुयोग्य श्रेणी के लाभुकों को सरकारी भूमि के बंदोबस्ती प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत 01 करोड़ 60 लाख रुपये का सांकेतिक चेक, मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत एक-एक लाख रुपये के अनुदान राशि मुख्यमंत्री कृषि यानिकी प्रजाति प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 01 लाख 28 हजार 700 रुपये का सांकेतिक चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने सतत् जीविकोपार्जन योजना से लाभान्वित 703 परिवारों को 02 करोड़ 66 लाख 24 हजार 200 रुपये तथा 12,743 जीविका स्वयं सहायता समूह को 129 करोड़ 75 लाख रुपये का सांकेतिक चेक प्रदान किया। सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत ई-रिक्शा हस्तांतरण की चाबी, जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत जीविका ग्राम संगठन आदर्श, चौगाई तथा सूरज इटाढ़ी में तालाब के जीर्णोद्धार के लिये 02 लाख 10 हजार रुपये हस्तांतरित करने की स्वीकृति पत्र लाभुकों को प्रदान किया।

देशज ज्ञान से सीखना होगा भीड़ प्रबंधन

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

प्रचार का प्रभाव और पर्व विशेष में त्रिवेणी में डुबकी लगाने के उत्साह में मची भगदड़ में तीस लोगों के प्रयागराज के संगमत तट पर चले गए थे और अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज विशेष रेल में बैठने की भगदड़ में 18 लोग मारे गए। इन दोनों हादसों में महिलाओं की संख्या अधिक रही है। ये घटनाएं इसलिए घटीं, क्योंकि सुविधाजनक यात्रा और प्रयागराज कुंभ में आस्था की डुबकी के आकर्षण ने देश ही नहीं दुनिया से सनातन हिंदुओं को बुला लिया। भारतीय ही नहीं अनेक पश्चिमी देशों के नागरिकों ने भी त्रिवेणी में डुबकी लगाकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। फलतः 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग अब तक गंगा स्नान कर चुके हैं और करोड़ों इस आस में प्रयागराज की ओर बढ़ रहे हैं, कि उन्हें भी कुंभ में डुबकी का अवसर मिल जाए तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाए। किंतु जिस तरह से आकस्मिक दुर्घटनाएं देखने में आई हैं, उससे लगता है भीड़ प्रबंधन का गणित हमें देशज ज्ञान परंपरा से सीखना होगा।

उत्तरप्रदेश सरकार ने इस महाकुंभ में अपनी क्षमता से अधिक आवागमन के साधनों से लेकर अनेक तकनीकी प्रबंध किए हैं। लेकिन भीड़ के आगे सभी प्रबंध कमजोर साबित हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही दुनिया के इस सबसे बड़े मेले में देखने में आ रहा है। बावजूद दिल्ली की घटना रेल प्रशासन की लापरवाही के संकेत देती है। जब दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली रेलों के लिए 1 घंटे में 15 हजार टिकट बिक रहे थे, तब उसने रेलों की उपलब्धता से अधिक टिकट क्यों बेचे? वे टिकट यात्रियों को प्लेटफार्म पर जाने ही क्यों दिया? यदि रेल की क्षमता से अधिक यात्रियों को स्टेशन के भीतर नहीं घुसने दिया जाता तो शायद भगदड़ में निर्दोष श्रद्धालुओं को प्राण गंवाने नहीं पड़ते? दरअसल हमारे यहां विभाग कोई सा भी हो, अंत में संपूर्ण जिम्मेदारी और जवाबदेही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर छोड़ दिया जाता है। जबकि ये खुद कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं। वस्तुतः आस्था के अनियंत्रित आवेग में अनहोनी घट जाती है। देश के प्रशासनिक अमले ने इसी कुंभ में त्रिवेणी संगम में घटी घटना से भी कोई सबक लेते हुए सावधानियां नहीं बरती?

भारत में पिछले डेढ़ दशक के दौरान मंदिरों और अन्य धार्मिक आयोजनों में उम्मीद से कई गुना ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। जिसके चलते दर्शन-लाभ की जल्दबाजी व कुप्रबंधन से उपजने वाली भगदड़ व आगजनी का सिलसिला हर साल इस तरह के धार्मिक मेलों में देखने में आ रहा है। इसी प्रयाग के 2013 में संपन्न हुए कुंभ मेले में रेलवे स्टेशन पर बने पैदल पुल पर भगदड़ मचने से 42 लोगों की मौत हो गई थीं। 1954 में भी प्रयागराज के कुंभ में 3 फरवरी को मौनी अमावस्या पर भगदड़ मची और 800 लोग काल के गाल में समा गए। 1986 में हरिद्वार के कुंभ में वीआईपी दर्जे के लोगों को विशेष स्नान के लिए भीड़ रोक देने के कारण भगदड़ मची और 200 लोग मारे गए थे। 2003 के नासिक कुंभ में 39 और 2010 के हरिद्वार के कुंभ में शाही स्नान के दौरान भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौतें हुई थीं। साफ है, प्रत्येक कुंभ में जानलेवा घटनाएं घटती रहने के बावजूद शासन-प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिए। धर्म स्थल हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम कम से कम शालीनता और आत्मानुशासन का परिचय दें। किंतु इस बात की परवाह आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं होती, अतएव उनकी जो सजगता घटना के पूर्व सामने आनी चाहिए, वह अक्सर देखने में नहीं आती? लिहाजा आजादी के बाद से ही राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र उस अनियंत्रित स्थिति को काबू करने की कोशिश में लगा रहता है, जिसे वह समय पर नियंत्रित करने की कोशिश करता तो हालात कमोबेश बेकाबू ही नहीं हुए होते? आयोजन को सफल बनाने में जुटे अधिकारी भीड़ के मनोविज्ञान का आंकलन करने में चूकते दिखाई देते हैं।

इस कुंभ की तैयारियों के लिए कई हजार करोड़ की धनराशि खर्च की गई। जरूरत से ज्यादा प्रचार करके लोगों को कुंभ स्नान के लिए आमंत्रित किया गया। फलतः कौने-कौने से श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाने का मन बना लिया। नतीजा यह निकला कि जिसे जो आवागमन का साधन मिला प्रयागराज की ओर चल दिया। जनसैलाब इतनी बड़ी संख्या में उमड़ा कि परिवहन से लेकर प्रयाग में प्रबंधन के सभी साधन कम पड़ गए। करोड़ों की भीड़ को संभालने के लिए सात स्तरीय सुरक्षा प्रबंधों से लेकर जो भी आधुनिक तकनीकि उपाय किए गए थे, वे सब ध्वस्त हो गए। ऐसा मेले के विराट रूप में बदल जाने के कारण हुआ। वैसे भी हमारे धार्मिक-आध्यात्मिक आयोजन विराट रुप लेते जा रहे हैं। कुंभ मेलों में तो विशेष पर्वों के अवसर पर एक साथ कई करोड़ लोग एक निश्चित समय के बीच स्नान करते हैं। ऐसे में भीड़ के अनुपात में यातायात और सुरक्षा के इंतजाम देखने में नहीं आते। जबकि शासन-प्रशासन के पास पिछले पर्वों के आंकड़े और अनुभव होते हैं। बावजूद लापरवाही और बदइंतजामी सामने आना चकित करती है। दरअसल, कुंभ या अन्य मेलों में जितनी भीड़ पहुंचती है और उसके प्रबंधन के लिए जिस प्रबंध कौशल की जरुरत होती है, उसकी दूसरे देशों के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते? इसलिए हमारे यहां लगने वाले मेलों के प्रबंधन की सीख हम विदेशी साहित्य और प्रशिक्षण से नहीं ले सकते? क्योंकि दुनिया के किसी अन्य देश में किसी एक दिन और विशेष मुहूत्र के समय लाखों-करोड़ों की भीड़ जुटने की उम्मीद ही नहीं की जाती? बावजूद हमारे नौकरशाह भीड़ प्रबंधन का प्रशिक्षण लेने खासतौर से यूरोपीय देशों में जाते हैं। प्रबंधन के ऐसे प्रशिक्षण विदेशी सैर-सपाटे के बहाने हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे प्रबंधनों के पाठ हमें खुद अपने देशज ज्ञान और अनुभव से लिखने होंगे। इस बार तो केवल प्रयागराज में ही नहीं उत्तरप्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाली सभी सड़कों पर कई-कई दिन जाम लगे रहे। नतीजतन सीमाई प्रांतों के प्रशासन को भी सजग रहना पड़ा।

प्रशासन के साथ हमारे राजनेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और आला अधिकारी भी धार्मिक लाभ लेने की होड़ में व्यवस्था को भंग करने का काम करते हैं। इनकी वीआईपी व्यवस्था और यज्ञकुण्ड अथवा मंदिरों में मूर्तिस्थल तक ही हर हाल में पहुंचने की रूढ़ मनोदशा, मौजूदा प्रबंधन को लाचार बनाने का काम करती है। नतीजतन भीड़ ठसाठस के हालात में आ जाती है। ऐसे में कोई महिला या बच्चा गिरकर अनजाने में भीड़ के पैरों तले रौंद दिया जाता है और भगदड़ मच जाती है। इस कुंभ में जहां केंद्रीय मंत्रीमंडल के मंत्री स्नान के लिए आते रहे, वहीं भाजपा शासित प्रदेश सरकारों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने भी वीआईपी घेरे में श्रद्धालुओं को परे करके डुबकी लगाई। बड़े व्यापारी घरानों ने भी परिवार सहित वीआईपी स्नान किए। कांग्रेस व अन्य दलों के दिग्गज नेता भी वीआईपी डुबकी लगा रहे हैं।

दरअसल दर्शन-लाभ और पूजापाठ जैसे अनुष्ठान अशक्त और अपंग मनुष्य की वैशाखी हैं। जब इंसान सत्य और ईश्वर की खोज करते-करते थक जाता है और किसी परिणाम पर भी नहीं पहुंचता है तो वह पूजापाठों के प्रतीक गढ़कर उसी को सत्य या ईश्वर मानने लगता है। यह मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी है। यथार्थवाद से पलायन अंधविश्वास की जड़ता उत्पन्न करता है। भारतीय समाज में यह कमजोरी बहुत व्यापक और दीर्घकालीक रही है। जब चिंतन मनन की धारा सूख जाती है तो सत्य की खोज मूर्ति पूजा और मुहूत्र की शुभ घड़ियों में सिमट जाती है। जब अध्ययन के बाद मौलिक चिंतन का मन-मस्तिष्क में ह्रास हो गया तो मानव समुदाय भजन-कीर्तन में लग गया। यही हश्र हमारे पथ-प्रदर्शकों का हो गया है। नतीजतन पिछले कुछ समय से सबसे ज्यादा मौतें भगदड़ की घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में उन श्रद्धालुओं की हो रही हैं, जो ईश्वर से खुशहाल जीवन की प्रार्थना करने धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं।

भीड़ बढ़ाने में सोशल मीडिया की भूमिका

धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ाने का काम सोशल मीडिया भी कर रहा है। इस कुंभ में हम देख रहे है कि नीली आंखों वाली लड़की और आईआईटिअन साधु के वीडियो एक तमाशे के रूप में कहीं ज्यादा दिखाए और देखे गए हैं। जबकि शंकराचार्यों से धर्म और आस्था के गूढ़ रहस्यों को ज्ञात करने की जरूरत थी? परंतु हमारे यहां प्रत्येक छोटे बड़े मंदिर के दर्शन को चमात्कारिक लाभ से जोड़कर देश के भोले-भाले भक्तगणों से एक तरह का छल मीडिया कर रहा है। इस मीडिया के अस्तित्व में आने के बाद धर्म के क्षेत्र में कर्मकांड और पाखण्ड का आडंबर जितना बढ़ा है, उतना पहले कभी देखने में नहीं आया। इसकी पृष्ठभूमि में बाजारवाद की भूमिका भी रहती है। हालांकि यही मीडिया पाखंड के सार्वजनिक खुलासे के बाद मूर्तिभंजक की भूमिका में भी खड़ा हो जाता है।

मीडिया का यही नाट्य रूपांतरण अलौकिक कलावाद, धार्मिक आस्था के बहाने व्यक्ति को निष्क्रिय व अंधविश्वासी बनाता है। यही भावना मानवीय मसलों को यथास्थिति में बनाए रखने का काम करती है और हम ईश्वरीय अथवा भाग्य आधारित अवधारणा को भाग्य का प्रतिफल व नियति का कारक मानने लग जाते हैं। दरअसल मीडिया, राजनेता और बुद्धिजीवियों का काम लोगों को जागरूक बनाने का है, लेकिन निजी लाभ का लालची मीडिया, लोगों को धर्मभीरू बना रहा है। राजनेता और धर्म की आंतरिक आध्यात्मिकता से अज्ञान बुद्धिजीवी भी धर्म के छद्म का शिकार होते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि पिछले दो दशक के भीतर मंदिर हादसों में लगभग 5000 से भी ज्यादा भक्त मारे जा चुके हैं। बावजूद श्रद्धालु हैं कि दर्शन, आस्था, पूजा और भक्ति से यह अर्थ निकालने में लगे हैं कि इनको संपन्न करने से इस जन्म में किए पाप धुल जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। गोया, पुनर्जन्म हुआ भी तो श्रेष्ठ वर्ण में होने के साथ आर्थिक रूप से समृद्ध व वैभवशाली होगा। परंतु इस तरह के खोखले दावों का दंभ हर मेले में ताश के पत्तों की तरह बिखरता दिखाई दे रहा है। जाहिर है, धार्मिक दुर्घटनाओं से छुटकारा पाने की कोई उम्मीद निकट भविष्य में दिखाई नहीं दे रही है?

जल संचय समय की मांग है

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

सभी जानते हैं कि आज जल संकट से पूरी दुनिया जूझ रही है। वह जल हो, नदी हो, वातावरण हो, वायु हो या हमारे उत्पाद स्रोत, सभी साझीदार हैं। पिछले कुछ दशकों में जल संकट ने विकराल रूप ले लिया है। देश के कई हिस्सों में वर्षा की अनियमितता, भूजल स्तर में गिरावट और बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की उपलब्धता गंभीर चिंता का विषय बन गई है। वर्तमान में भूजल स्तर में तेजी से बढ़ रही गिरावट और भूजल की गुणवत्ता जहां एक भयावह खतरे का एक संकेत है वहीं पीने के लायक साफ पानी की कमी के भीषण संकट के चेतावनी भी है। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि पवित्र कंखले गंगा कुरुक्षेत्रे सरस्वती, वा ग्रामे या आरण्य पवित्र सर्वत्र नर्मदा। जल की शक्ति है कि उसके आधार पर एक पूरी संस्कृति निर्मित हो सकती है और उसके अभाव में पूरा क्षेत्र नष्ट हो सकता है। इस लिए इस शक्ति को समझना मनुष्य के लिए जीवन मरण का प्रश्न है।

ऐसे में वर्षा जल संचय (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) एक प्रभावी समाधान के रूप में उभरकर सामने आया है। जल ही जीवन है, यह उक्ति अब केवल कहावत नहीं रह गई है, बल्कि हमारी वास्तविकता बन चुकी है। तेजी से घटते जल स्रोतों और बदलते जलवायु परिवर्तनों ने हमें चेतावनी दी है कि यदि अब भी हमने जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया, तो भविष्य में पीने योग्य पानी की भारी किल्लत हो सकती है। विशेष रूप से शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव और अनियंत्रित जल दोहन ने स्थिति को और भी भयावह बना दिया है। ऐसे में वर्षा जल संचय न केवल एक वैकल्पिक उपाय है, बल्कि यह हमारी सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी भी बन गई है।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में वर्षा जल का सही तरीके से संरक्षण न कर पाना हमारे विकास में एक बड़ी बाधा बन सकता है। जहां एक ओर मानसून में बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के कारण पानी बर्बाद हो जाता है, वहीं दूसरी ओर गर्मी के मौसम में जल संकट अपने चरम पर पहुंच जाता है। इसका मुख्य कारण जल प्रबंधन की कमजोर नीतियां और वर्षा जल संचय की अनदेखी है। पारंपरिक जल स्रोत जैसे तालाब, कुएं और बावड़ियों का रखरखाव न होने के कारण ये धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं। वहीं, अंधाधुंध भूजल दोहन के कारण कई शहरों में जल स्तर अत्यधिक नीचे चला गया है। भूजल स्तर के गिरने से जल संकट और भी गहरा हो रहा है। ऐसे में वर्षा जल संचय एकमात्र उपाय है, जिससे इस समस्या को हल किया जा सकता है। वर्षा जल संचय के विभिन्न तरीके अपनाकर जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इनमें कुछ प्रमुख उपाय हैं जैसे वर्षा जल को छतों पर एकत्र कर टैंकों में संग्रहित किया जा सकता है, जिसे बाद में घरेलू उपयोग, बागवानी और अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वर्षा जल को धरती में समाहित करने के लिए सोख गड्ढे (पिट), परकोलेशन टैंक और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, जिससे भूजल स्तर को पुनर्भरित किया जा सके। गांवों और शहरों में छोटे-छोटे तालाब और जलाशय बनाकर वर्षा जल को संरक्षित किया जा सकता है, जिससे सिंचाई और जलापूर्ति सुगम हो सके। इसके अलावा पुराने कुओं, बावड़ियों और तालाबों को पुनर्जीवित कर उनमें वर्षा जल एकत्र किया जा सकता है, जिससे भूजल स्तर को बनाए रखा जा सकता है।

वर्षा जल के बहाव को संरक्षित करने और उसे नष्ट होने से बचाने के लिए नालों, नहरों और अन्य जल निकासी संरचनाओं का सही रखरखाव आवश्यक है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वर्षा जल संचय अत्यंत महत्वपूर्ण है। शहरों में बढ़ते कंक्रीट जंगल और जलाशयों के अतिक्रमण के कारण जल संरक्षण की समस्या अधिक गंभीर होती जा रही है। शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल को संग्रहित करने से भूजल पुनर्भरण में सहायता मिलती है और पेयजल संकट को कम किया जा सकता है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है। वर्षा जल संचय से किसानों को सूखे के समय मदद मिल सकती है, जिससे खेती की निर्भरता केवल मानसून पर न रहकर जल संरक्षण उपायों पर भी हो। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। सरकार ने जल संरक्षण को लेकर कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें 'जल जीवन मिशन', 'अटल भूजल योजना' और 'कैच द रेन' जैसी पहलें शामिल हैं। विभिन्न राज्यों में वर्षा जल संचय को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। कई जगहों पर वर्षा जल संचयन को भवन निर्माण अनुमति का अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया है, जिससे लोग जल संरक्षण के प्रति अधिक सचेत हो रहे हैं। सरकारी प्रयासों के साथ-साथ आम जनता की भागीदारी भी आवश्यक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर, कॉलोनी और समाज में वर्षा जल संचय को अपनाने का प्रयास करे, तो जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सामूहिक प्रयासों के बिना जल संरक्षण संभव नहीं है। हमें जल बचाने की आदत डालनी होगी और अनावश्यक जल अपव्यय को रोकना होगा। वर्षा जल संचय की दिशा में स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं को भी जागरूकता अभियान चलाने होंगे, जिससे नई पीढ़ी इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा सके।

जल संकट एक गंभीर मुद्दा है और इससे निपटने के लिए वर्षा जल संचय सबसे प्रभावी समाधान है। यह न केवल भूजल स्तर को संतुलित बनाए रखने में सहायक है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को जल संकट से बचाने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। सरकार, सामाजिक संगठनों और आम जनता को मिलकर इस दिशा में कार्य करना होगा। यदि हम अभी से जल संरक्षण के प्रति सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में जल का संकट और भी भयावह हो सकता है। इसलिए, वर्षा जल संचय को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और जल संरक्षण में योगदान दें

स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर विशेष

स्वामी दयानंद सरस्वती : समाज सुधार के अग्रदूत

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

19वीं सदी के महान समाज सुधारक और दार्शनिक, स्वामी दयानंद सरस्वती की आज जयंती है। उनका जन्म 1824 में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को हुआ था। जो इस वर्ष 23 फरवरी को है। वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। 1875 में, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करना और समाज में फैली बुराइयों को दूर करना था। जिसके माध्यम से कई कुरितियों का अंत हुआ और लोगों में जागरूकता आई। आर्य समाज के माध्यम से आज भी वैदिक ज्ञान, शिक्षा और पूजन-हवन की सीख दी जा रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उनके विचारों ने लोगों को जागरूक किया और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद की। उन्हें एक महान समाज सुधारक, दार्शनिक और शिक्षाविद के रूप में याद किया जाता है। आर्य समाज आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को आगे बढ़ा रहा है। यह संगठन वैदिक ज्ञान, शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

प्रारंभिक जीवनः स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर अंबाशंकर तिवारी था। उनके पिता करशनजी लालजी तिवारी एक टैक्स कलेक्टर होने के साथ-साथ एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम यशोदाबाई था। स्वामी दयानंद बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने 2 साल की आयु में ही गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना सीख लिया था। उनके परिवार में पूजा-पाठ और शिव-भक्ति का धार्मिक माहौल था, जिसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने बचपन से ही वेदों, शास्त्रों, धार्मिक पुस्तकों और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया।

घर का त्यागः 21 साल की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया और जीवन-मृत्यु के चक्र की सच्चाई जानने के लिए संन्यासी बनने का फैसला लिया। उन्होंने अपने विवाह के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। उनके पिता के साथ कई बार बहस हुई, लेकिन स्वामी जी के दृढ़ फैसले के आगे उनके पिता को भी झुकना पड़ा।

गुरु की खोज और ज्ञान प्राप्तिः उन्होंने मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से योग विद्या, शास्त्र और आर्ष ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब गुरु दक्षिणा देने की बात आई, तब उनके गुरु विरजानंद जी ने उनसे समाज में फैली कुरीति, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ काम करने और आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कहा। मानव कल्याण के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती 30 अक्टूबर 1883 को परम ब्रह्म में विलीन हो गए।

1857 के स्वतंत्रता संग्राम में योगदानः स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने लोगों को अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ जागरूक किया और उन्हें एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पूर्ण स्वराज हासिल करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनके विचारों से कई महान स्वतंत्रता सेनानी प्रभावित हुए।

स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान

* **वेदों का पुनरुद्धारः** उन्होंने वेदों के ज्ञान को पुनः स्थापित करने पर जोर दिया और लोगों को वेदों के सच्चे अर्थ को समझने के लिए प्रेरित किया।
* **आर्य समाज की स्थापनाः** 1875 में, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करना और समाज में फैली बुराइयों को दूर करना था।
* **कुरितियों का विरोधः** उन्होंने बलि प्रथा, झूठे कर्मकांड, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और छुआछूत जैसी कुरीतियों का कड़ा विरोध किया।
* **शिक्षा का प्रसारः** उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझते हुए गुरुकुलों की स्थापना की और वैदिक शिक्षा को बढ़ावा दिया।
* **सत्यार्थ प्रकाश की रचनाः** उन्होंने "सत्यार्थ प्रकाश" नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिसमें उनके विचार और दर्शन संग्रहित हैं।

स्वामी दयानंद सरस्वती के महत्वपूर्ण विचार

* "वेदों में वर्णित सार का पान करने वाले ही यह जान सकते हैं कि जिंदगी का मूल बिंदु क्या है।"
* "क्रोध का भोजन विवेक है, अतः इससे बचके रहना चाहिए। क्योंकि विवेक नष्ट हो जाने पर, सब कुछ नष्ट हो जाता है।"
* "अहंकार एक मनुष्य के अंदर वह स्थिति लाती है, जब वह आत्मबल और आत्मज्ञान को खो देता है।"
* "ईर्ष्या से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए। क्योंकि यह मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाती रहती है और पथ से भटकाकर पथभ्रष्ट कर देती है।"
* "अगर मनुष्य का मन शांत है, चित्त प्रसन्न है, हृदय हर्षित है, तो निश्चय ही यह अच्छे कर्मों का फल है।"

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल 2025

मोदी को मोहित करने में लगे मोहन यादव

एक आंकलन के अनुसार इस समिट के लिए मोहन यादव सरकार ने लगभग 1500 करोड़ खर्च किये है। यह राशि मध्यप्रदेश जैसे कर्जेलू राज्य के लिए काफी होती है लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को मोहित करने और अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए सरकार का खजाना ही खोल दिया है। भले ही यह खजाना कर्ज से भरा हो। जबकि आज प्रदेश के हालात ऐसे है कि प्रदेश सरकार प्रतिमाह 05 हजार करोड़ का कर्ज ले रही है। यदि इन समिट के परिणाम देखें तो तस्वीर कुछ दूसरी ही नजर आती है। आंकड़ों में भले ही बताया जाता है कि प्रदेश में प्रत्येक समिट से लाखों करोड़ों के निवेश प्रस्ताव आये हैं। लाखों युवाओं को रोजगार मिला है लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी जाती है तो तस्वीर काफी धुंधली नजर आती है।

-विजया पाठक

आज से भोपाल में दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। इसके साथ ही देश-विदेश के कई निवेशक, उदयोगपति भी समिट में शिरकत करने वाले हैं। पिछले कई महिनों से इस समिट की तैयारियां की जा रही थी। निवेशकों को आमंत्रित करने मुख्यमंत्री मोहन यादव देश के तमाम शहरों के अलावा विदेश तक गये। इसके साथ ही आयोजन स्थल भोपाल को दुल्हन की तरह संजाया, संवारा गया है। एक आंकलन के अनुसार इस समिट के लिए मोहन यादव सरकार ने लगभग 1500 करोड़ खर्च किये हैं। यह राशि मध्यप्रदेश जैसे कर्जेलू राज्य के लिए काफी होती है लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को मोहित करने और अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए सरकार का खजाना ही खोल दिया है। भले ही यह खजाना कर्ज से भरा हो। जबकि आज प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि प्रदेश सरकार प्रतिमाह 05 हजार करोड़ का कर्ज ले रही है। हम जानते हैं कि किसी भी सरकार का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना होना चाहिए। इस दृष्टि से, निवेश आकर्षित करना एक महत्वपूर्ण पहल है। लेकिन यहां सवाल दूसरा ही है। प्रदेश में यह पहली समिट नही है। इससे पहले भी दर्जनों समिट हुई हैं। यदि इन समिट के परिणाम देखें तो तस्वीर कुछ दूसरी ही नजर आती है। आंकड़ों में भले ही बताया जाता है कि प्रदेश में प्रत्येक समिट से लाखों करोड़ों के निवेश प्रस्ताव आये हैं। लाखों युवाओं को रोजगार मिला है लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी जाती है तो तस्वीर काफी धुंधली नजर आती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सिर्फ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने से विकास नहीं होगा, जब तक कि उन पर धरातल पर प्रभावी अमल नहीं किया जाता। पिछले इन्वेस्टर समिट में जो वादे किए गए थे, वे आज तक अधूरे हैं। कई उद्योगों की घोषणाएँ की गईं, लेकिन ज्यादातर या तो शुरू ही नहीं हो पाईं या फिर अधर में लटकी रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा आयोजित छह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इन आयोजनों में बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो हुईं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कांग्रेस ने दावा किया कि इन समिट में राज्य का पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन निवेश नाममात्र का ही आया।

सरकार समिट के नाम पर करोड़ों का कर्ज लेकर ब्रांडिंग पर ज्यादा खर्च करती है। इस समिट के लिए मोहन सरकार पानी के तरह पैसा बहाया है। मध्यप्रदेश में मोहन यादव इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर अरबों रुपये बर्बाद किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने आपको स्थापित करने के चक्कर में प्रदेश की खस्ता हालत को और खस्ता करने पर तुले हैं। इससे पहले भी प्रदेश में इन्वेस्टर्स समिट हुई हैं। मोहन सरकार में ही कोई सात समिट हो चुकी हैं। यह आठवीं समिट है। अब इन सात समिट की बात की जाये तो अभी तक कोई भी उदयोग जमीन पर नहीं उतरा है। लेकिन आज सवाल फिर वही उठ रहा है कि आखिर जब समिट का आउटपुट नहीं निकल रहा है तो समिट करने का क्या मतलब। इन समिट में भी प्रदेश सरकार का अरबों रूपये खर्च होता है। पूरा प्रशासन कई दिन पहले से तैयारियां करता है। आज मोहन यादव के कार्यों का अवलोकन करें तो एक तरफ वो इन्वेस्टर्स समिट कर रहे हैं, वहीं प्रदेश के युवा उद्यमी अपना स्टार्ट-अप को प्रदेश में बंद कर अपना बोरिया बिस्तर समेट कर दूसरे प्रदेश चले गए हैं। जैसे कि युवा उद्यमी प्रतीक और दीपेश ने अपनी स्टार्ट-अप वंडर लूम्स को मध्य प्रदेश में सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने के कारण प्रदेश छोड़ना पड़ा। वहीं यह स्टार्ट-अप अब पुणे में बहुत अच्छा कर रही है। मैंने पहले भी प्रदेश के मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल का भी छापा था, जहां मोहन यादव ने अधिकारी नहीं पदस्त करने के कारण प्रदेश में 50 दिनों तक उद्योग नहीं लगने दिया, ऐसे में आश्चर्य नहीं होगा कि कागजों में तो निवेश दिखाया जाएगा पर वास्तविक जमीन पर कुछ उतरने वाला नहीं है। दिक्कत यह है कि मोहन यादव का विजन सिर्फ पैसा कमाने का रहा है, ना उनका दायरा बड़ा था, ना व्यापक। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने के बाद पिछले स्वा साल में कोई खास उपलब्धि भी हासिल नहीं की है। ऐसे में ऐसा दिखावा तो करना ही पड़ेगा भले ही प्रदेश का दिवाला निकल जाये।

पिछली समिट का आउटपुट क्या निकला?

अगर हम 2003 से अब तक के 06 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का रिकॉर्ड देखें, तो जमीनी स्तर पर सफलता दर शून्य प्रतीत होती है। 2003 से 2016 तक पहले पांच निवेशक सम्मेलनों में 17.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों का दावा किया गया था। इसके बाद 2023 में इंदौर में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लगभग 15.40 लाख करोड़ रुपये के निवेश का दावा किया। यानी लगभग 32 लाख करोड़ रुपये का निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर आने का दावा किया गया। जबकि हकीकत यह है कि 2003 से 2023 तक केवल 3.47 लाख करोड़ रुपये ही आए, जो सरकार द्वारा प्राप्त कुल निवेश प्रस्तावों का केवल 10% है। 06 समिट के कुल निवेश का केवल 10 प्रतिशत काम हुआ। 29 लाख रोजगार का दावा था, मिले सिर्फ 38 हजार। एसोचैम की अगस्त 2024 की रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदेश में अधिकांश नए निवेश अभी शुरू नहीं हुए। पिछले वित्त वर्ष में नए निवेश में 14% गिरावट आई है।

विदेशी निवेश में दूसरे राज्यों से मप्र बहुत पीछे

विदेशी निवेश के मामले में दूसरे राज्यों से मध्यप्रदेश बहुत पीछे है। अक्टूबर 2019 से सितंबर 2022 के बीच हुए निवेश की एक रिपोर्ट के आधार पर बताया कि मप्र में 0.33 फीसदी निवेश ही हुआ है। विदेशी निवेश के मामले में प्रदेश को टॉप 10 राज्य से बाहर बताया। केवल जीआई टैग देने से कैसे काम चलेगा। आपको मार्केट भी तो बनाना पड़ेगा।

भाजपा सरकार की 06 समिट के आंकड़े

2007 में पहली जीआईएस हुई, जिसमें 1.20 लाख करोड़ निवेश का प्रस्ताव मिला, लेकिन 17311 करोड़ रुपए ही निवेश हुए।

दूसरी इंवेस्टर्स समिट 2010 में हुई और इसमें 2.35 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया था, लेकिन 26879 करोड़ रुपए ही आए।

तीसरी जीआईएस 2012 में हुई और इसमें 26054 करोड़ के प्रस्ताव आए। जबकि 3.50 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले थे

2014 में हुई समिट के बाद 49,272 करोड़ रुपए के निवेश हुए। जबकि कुल प्रस्ताव 4.35 लाख करोड़ के आए थे।

2016 में 5.63 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए और निवेश हुआ 32597 करोड़ का।

2023 में 15.42 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए थे और 1.95 लाख करोड़ रुपए का ही निवेश हुआ।

आखिर इतना खर्च कर क्या होगा फायदा?

विशेषज्ञों की मानें तो जब मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले एक साल में सात संभागीय मुख्यालयों में क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव आयोजित किये और इतनी बड़ी संख्या में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त किये तो फिर जीआईएस की आवश्यकता क्यों पड़ी। जीआईएस का आयोजन कहीं न कहीं एक ओर यह साबित करता है कि सरकार और मुख्यमंत्री यादव को ने क्षेत्रीय समिट के नाम से जो भी घोषणाएं निवेश प्राप्ति हो लेकर की है यह सभी खोखली हैं और अब उन पर पर्दा डालने के लिये जीआईएस के आयोजन की श्रृंखला शुरू की है। एक बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर जीआईएस जैसे इतने बड़े आयोजन की आवश्यकता क्यों है। आखिर सरकार जनता के टैक्स के करोड़ों रुपयों को इस तरह से आयोजन के नाम पर क्यों बर्बाद कर रही है। आखिर जनता के पैसों की बर्बादी का यह सिलसिला कब रुकेगा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)